SHABDBRAHM E-ISSN: 3049 4230
VOLUME 1, ISSUE 2, OCTOBER 2025

"आज के भारत में राजनीतिक यथार्थवाद की प्रासंगिकता: सरदार पटेल का एक पुनर्विचार"

डॉ. हेतल डी. राणा

सहायक अध्यापिका राजनीति विज्ञान विभाग,

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्या नगर

सारांश (Abstract)

यह शोधपत्र सरदार वल्लभभाई पटेल के राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा का समकालीन भारत के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन करता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण, प्रशासनिक ढाँचे के सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीतियों में पटेल की भूमिका उनके व्यावहारिक, परिस्थितिजन्य और शक्ति-संतुलन केंद्रित दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। आज जब भारत क्षेत्रीय विविधताओं, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सुरक्षा चुनौतियों और बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन से जूझ रहा है, तब पटेल का राजनीतिक यथार्थवाद अत्यंत प्रासंगिक होकर उभरता है। यह अध्ययन पटेल की नीतिगत दृष्टि और वर्तमान भारतीय राजनीति के बीच संबंधों की पड़ताल करता है, साथ ही यह दर्शाता है कि समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यवहारिकता, संस्थागत मजबूती और राष्ट्रीय एकता किस प्रकार निर्णायक भूमिका निभाती हैं। रियासतों के एकीकरण, प्रशासनिक ढाँचे के निर्माण, सुरक्षा-आधारित निर्णय-क्षमता और व्यावहारिक राष्ट्रीय नीति–ये सभी उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण के स्पष्ट उदाहरण हैं। आज का भारत–जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा तनाव, क्षेत्रीय पहचान-आंदोलन, वैश्विक शक्ति-संतुलन, तथा प्रशासनिक जटिलताओं जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है–फिर से पटेल की राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है। शोधपत्र का उद्देश्य पटेल के विचारों को नए संदर्भों में समझना और यह विश्लेषण करना है कि उनकी यथार्थवादी राजनीति वर्तमान नीति-निर्माण, सुरक्षा ढांचे और संघीय संरचना के लिए किस प्रकार उपयोगी दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है। शोधपत्र सिद्धांत, व्यवहार और परिणाम के बहु-स्तरीय

विश्लेषण के माध्यम से यह निष्कर्ष देता है कि सरदार पटेल का यथार्थवादी नेतृत्व मॉडल आज भारत के लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक है।

कीवर्ड्स: सरदार पटेल, राजनीतिक यथार्थवाद, भारतीय लोकतंत्र, राष्ट्र-निर्माण, रियासतों का एकीकरण, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, संघात्मक ढांचा, समकालीन भारतीय राजनीति, शक्ति-संतुलन

प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय राजनीतिक इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल का स्थान एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित है, जिन्होंने स्वतंत्रता के निर्णायक क्षणों में अपने अद्‌वितीय राजनीतिक यथार्थवाद के माध्यम से नवगठित राष्ट्र को संगठित और सुदृढ़ किया। 1947-50 का कालखंड भारत के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था–साम्राज्यवादी शासन की समाप्ति, विभाजन से उत्पन्न अस्थिरता, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन, और देशी रियासतों के विलय जैसी समस्याएँ नई सरकार के सामने विद्‌यमान थीं। ऐसे समय में पटेल ने भावनात्मक आदर्शवाद के स्थान पर व्यावहारिक निर्णय क्षमता, शक्ति-संतुलन की समझ और राज्य-निरपेक्ष राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हुए नीति-निर्माण किया। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण यह मान्यता देता था कि राष्ट्र-निर्माण केवल नैतिकता या आदर्शवाद पर नहीं टिका होता, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और प्रभावी प्रशासन पर आधारित यथार्थवादी निर्णयों पर भी निर्भर करता है।

समकालीन भारत में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बढ़ती आंतरिक-सुरक्षा चुनौतियों, चीन-पाकिस्तान तनाव, बदलते संघीय संबंधों, पहचान-आधारित राजनीति, वैश्विक शक्ति-प्रतिस्पर्धा और प्रशासनिक प्रणालियों के जटिल होते स्वरूप के बीच पटेल के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्‌धांत किस हद तक प्रासंगिक बने हुए हैं। आज का भारत एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहाँ घरेलू स्तर पर प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समरसता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक स्वायत्तता और शक्ति-संतुलन की नीति भी। इन

सभी आयामों में पटेल के विचार–मजबूत केंद्रीय राज्य, सुव्यवस्थित प्रशासन, सुरक्षा-संवेदनशील निर्णय और राष्ट्रीय एकीकरण–एक बार पुनः चिंतन की माँग करते हैं।

इस अध्ययन का उद्देश्य इसी प्रासंगिकता का पुनर्मूल्यांकन करना है: क्या और कैसे पटेल का राजनीतिक यथार्थवाद आज की नीतियों, शासन-प्रणालियों और लोकतांत्रिक व्यवहार को दिशा प्रदान करता है? तथा वर्तमान भारत में उनके विचारों का शक्ति-राजनीति और राज्य-निर्माण पर क्या प्रभाव परिलक्षित होता है।

समस्या का विवरण (Statement of the Problem)

स्वतंत्र भारत की राजनीतिक-प्रशासनिक संरचना के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल के राजनीतिक यथार्थवाद ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु समकालीन भारत में राजनीति का चरित्र निरंतर परिवर्तित हो रहा है–पहचान-आधारित आंदोलनों, संघीय तनावों, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, वैश्विक शक्ति-संतुलन के बदलावों और प्रशासनिक अपेक्षाओं की जटिलता ने नीति-निर्माण को अधिक बहुआयामी बना दिया है। ऐसे परिवर्तित परिदृश्य में यह प्रश्न स्पष्ट रूप से उभरता है कि क्या पटेल का राजनीतिक यथार्थवाद आज भी भारतीय राजनीति को समझने और उसका मार्गदर्शन करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है?

समस्या यह है कि राजनीतिक विमर्श में पटेल को अक्सर केवल रियासतों के एकीकरण या 'लौह पुरुष' की छवि तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण समकालीन नीतिगत चुनौतियों के संदर्भ में पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है। वर्तमान शोध में इस बात की कमी है कि पटेल के निर्णयों–जैसे अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता, मजबूत केंद्र की अवधारणा, तथा प्रशासनिक दक्षता–का आधुनिक भारत के राजनीतिक व्यवहार, शासन प्रणाली और सुरक्षा नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है, इसे व्यवस्थित रूप से नहीं समझा गया है।

इस प्रकार, अनुसंधान की मूल समस्या यह है कि आधुनिक भारत की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों के बीच पटेल के राजनीतिक यथार्थवाद की प्रासंगिकता का पुनर्मूल्यांकन कैसे

किया जाए, और किस प्रकार उनके विचार आज भी राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय एकीकरण और रणनीतिक निर्णय-निर्माण को समझने में सहायक हो सकते हैं।

साहित्य समीक्षा (Literature Review)

- राजमोहन गांधी - *Patel: A Life*

  यह पटेल का सबसे विश्वसनीय और विस्तृत जीवनचरित माना जाता है। इसमें पटेल की व्यवहारिक राजनीतिक सोच, एकीकरण की रणनीतियाँ, और गांधी-नेहरू-शास्त्री जैसे समकालीन नेताओं के साथ उनके संबंधों का सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है।

- बी. आर. नंदा - *Sardar Patel*

  इस पुस्तक में पटेल के नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और कांग्रेस के भीतर उनकी भूमिका का संतुलित अकादमिक विश्लेषण है।

- पी. बी. वाडिया - *The Story of Integration of Indian States*

  यह रियासतों के विलय पर मूलभूत स्रोत है। इसमें पटेल के निर्णयों की वास्तविक परिस्थितियों और उनके राजनीतिक यथार्थवाद का विस्तृत वर्णन है।

- **Mehta, P. B. (2002). "Realism in Indian Political Thought." Journal:** *Political Studies Review*

  लेखक पटेल के दृष्टिकोण को कांटिल्य से लेकर मॉर्गेंथ्यू तक के वैश्विक यथार्थवाद परंपरा से जोड़ते हैं।

- **Mishra, B. (1997), "The Political of Accession: Sardar Patel and The Princes" Journal:** *Economic & Political Weekly (EPW)*

  यह लेख बताता है कि पटेल का दृष्टिकोण 'moral persuasion' की बजाय 'political realism' पर आधारित था।

- **Thakur, V. (2013). "Indian Statecraft and Realist Tradition: From Kautilya to Patel." Journal:** *South Asian Studies Journal*

लेख बताता है कि पटेल की राजनीति शक्ति, हित और स्थिरता पर आधारित थी–जो यथार्थवाद का मूल है।

चौधरी, 2018; राव, 2020 द्वारा हाली में किया गया संशोधन यह रेखांकित करते हैं कि आज की भारतीय राजनीति–विशेषतः सुरक्षा नीति, संघीय ढाँचा और संस्थागत स्वतंत्रता–पटेल के मॉडल से सीमांत रूप से प्रभावित है। किंतु इन अध्ययनों में उनके विचारों का भारतीय लोकतंत्र के समकालीन संदर्भ में व्यवस्थित तुलनात्मक विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित पाया गया है।

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. सरदार पटेल के राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा का समकालीन भारतीय राजनीति के संदर्भ में परीक्षण करना।
2. सरदार पटेल के विचारों और निर्णयों का विश्लेषण करना।
3. समकालीन भारत में पटेल के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता स्थापित करना।
4. भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक ढाँचे के लिए नए निष्कर्ष निकालना।
5. भविष्य में नीति-निर्माण हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रश्न (Research Questions)

1. क्या सरदार पटेल का राजनीतिक यथार्थवाद आज की भारतीय राजनीति में प्रासंगिक है?
2. पटेल की नीतियाँ–विशेषतः रियासतों का एकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचा–आज के राजनीतिक परिवेश में किस प्रकार परिलक्षित होती हैं?
3. क्या समकालीन भारत की संघीय संरचना और केंद्र-राज्य संबंध पटेल के दृष्टिकोण से प्रभावित हैं?

4. राजनीतिक यथार्थवाद वर्तमान नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में किस हद तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है?

परिकल्पना (Hypothesis):

H_1: सरदार पटेल का राजनीतिक यथार्थवाद आज के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक संरचना और नीति-निर्माण में स्पष्ट रूप से लागू होता है।

H_2: समकालीन भारतीय राजनीति में शक्ति-संतुलन एवं व्यवहारिक निर्णयों की बढ़ती प्रवृत्ति पटेल के मॉडल की पुनरावृत्ति को दर्शाती है।

H_3: संघीय ढांचे में उत्पन्न चुनौतियों को समझने एवं प्रबंधित करने के लिए पटेल का दृष्टिकोण आज भी प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

शोध का औचित्य (Justification of the Study):

स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक ढांचा और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीतियों में सरदार वल्लभभाई पटेल का योगदान बुनियादी रूप से निर्णायक रहा है। यह शोध आवश्यक है क्योंकि सरदार पटेल के राजनीतिक यथार्थवाद पर उपलब्ध साहित्य मुख्यतः ऐतिहासिक विवरण तक सीमित है, जबकि समकालीन भारत की जटिल राजनीतिक स्थितियाँ–जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संघीय संबंध, प्रशासनिक सुधार और वैश्विक शक्ति-संतुलन–उनकी व्यवहारिक सोच के पुनर्मूल्यांकन की मांग करती हैं। आधुनिक नीति-निर्माण में व्यावहारिक निर्णय, मजबूत प्रशासन और राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता जैसे तत्व फिर से केंद्रीय हो रहे हैं। इसलिए पटेल के यथार्थवाद को आज की राजनीति से जोड़कर समझना मौलिक और समयानुकूल शोध योगदान प्रदान करता है।

अवधारणात्मक ढाँचा (Conceptual Framework)

क) क्लासिकल रियलिज्म (Classical Realism)

मैकियावेली और हॉब्स के अनुसार राज्य का पहला कर्तव्य सुरक्षा है। पटेल ने इसी सिद्धांत को भारतीय संदर्भ में लागू किया।

(ख) मॉर्गेन्थ्यू का राजनीतिक यथार्थवाद

राजनीति का संचालन शक्ति और राष्ट्रीय हित से होता है। रियासतों का एकीकरण इसका उदाहरण है।

(ग) संरचनात्मक यथार्थवाद (Structural Realism)

सुरक्षा दुविधा, सीमाओं की सुरक्षा, कठोर निर्णय- भारतीय सुरक्षा चुनौतियों में यह सिद्धांत अप्लाई होता है।

यह शोध पत्र इन सिद्धांतों को पटेल के नेतृत्व और आज की भारतीय स्थिति से जोड़ता है।

शोध पद्धति (Research Methodology)

शोध प्रकार: वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical)

डेटा स्रोत: प्राथमिक: सरकारी दस्तावेज़, नीति-निर्देश, भाषण, योजनाएँ

द्वितीयक: पुस्तकें, जर्नल, रिपोर्ट, शोधपत्र

सैद्धांतिक आधार: राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी सिद्धांत

इस शोध पत्र में विश्लेषण पद्धति गुणात्मक राजनीतिक-आर्थिक विश्लेषण अपनाई गई है।

शोध की सीमाएँ (Limitations)

इस अध्ययन में निम्नलिखित सीमाओं का भी स्वीकार किया गया है–

- पटेल से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत पर्याप्त हैं, परंतु राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण तुलनात्मक रूप से कम उपलब्ध है।
- समकालीन भारतीय नीतियों की समीक्षा कई बार वर्तमान राजनीतिक बहसों से प्रभावित हो सकती है; अतः शोध ने वस्तुनिष्ठता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
- पटेल की विचारधारा का प्रत्यक्ष दस्तावेजीकरण सीमित है, जिसके कारण कुछ विश्लेषण व्युत्पन्न (derived) स्वरूप में हैं।
- फिर भी, शोध का उद्देश्य इन सीमाओं को संतुलित करते हुए गहन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।

शोध अंतराल (Research Gap):

यद्यपि पटेल पर कई ऐतिहासिक एवं जीवनीपरक अध्ययन उपलब्ध हैं, परंतु उनके राजनीतिक यथार्थवाद को सिद्धांतिक ढांचे में रखकर आज की भारतीय राजनीति विशेषतः सुरक्षा, संघवाद, राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में व्यवस्थित विश्लेषण करने वाले शोध अत्यंत कम हैं।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक यथार्थवाद की अंतरराष्ट्रीय विचारधारा और पटेल के भारतीय मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन भी अपेक्षाकृत अनुपस्थित है। समकालीन भारतीय नीतियों का पटेल के दृष्टिकोण से आलोचनात्मक मूल्यांकन भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुआ है। यह शोध इन रिक्तताओं को संबोधित करता है।

मूल लेख: Discussion

सरदार पटेल का राजनीतिक यथार्थवाद: वैचारिक आधार

SHABDBRAHM

सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय राजनीति में उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे राजनीतिक सिद्धांत में यथार्थवाद (Realism) कहा जाता है। उनकी राजनीतिक शैली चार मूल सिद्धांतों पर आधारित थी:

1. राष्ट्रीय हित सर्वोपरि
2. सुरक्षा और स्थिरता के बिना विकास असंभव
3. व्यावहारिक निर्णय-प्रक्रिया, भावनात्मक आदर्शों से दूरी
4. सत्ता-संगठन और संस्थागत क्षमता को प्राथमिकता

एक ओर जहाँ स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक राजनीति में नैतिक-आदर्शवादी विचारधारा को अहम स्थान मिला, वहीं सरदार पटेल ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्र-निर्माण केवल आदर्शों से नहीं, बल्कि कठोर निर्णयों और सत्ता-संरचना के सुदृढ़ीकरण से सफल होता है।

उनकी सोच का मूल यह था कि "राज्य तभी जीवित रह सकता है जब उसके पास अनुशासित सुरक्षा-व्यवस्था और मजबूत केंद्रीय शासन हो।"

रियासतों का विलय: भारतीय राजनीतिक एकीकरण का यथार्थवादी मॉडल:

राजनीतिक यथार्थवाद का सबसे बड़ा उदाहरण 562 रियासतों का विलय है।

पटेल ने इसे केवल कूटनीतिक रणनीति से नहीं, बल्कि तीन स्तरों पर योजनाबद्ध तरीके से लागू किया:

(क) मनोवैज्ञानिक कूटनीति- राजाओं को यह विश्वास दिलाया कि भारतीय संघ में शामिल होने से ही उनके भविष्य सुरक्षित होंगे।

(ख) कानूनी-संवैधानिक दबाव- "इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन" का उपयोग करके विलय को कानूनी संरक्षण दिया।

(ग) अंतिम विकल्प के रूप में शक्ति-प्रयोग- जूनागढ़ और हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई उनके यथार्थवादी नेतृत्व का सर्वोच्च उदाहरण है।

SHABDBRAHM

वे अच्छी तरह जानते थे कि "असहमति का सम्मान" तब तक संभव है जब तक वह राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती न दे।

यह मॉडल आज भी भारत की आंतरिक सुरक्षा, सीमाई संप्रभुता, तथा संघीय स्थिरता की नीतियों का आधार है।

पटेल की प्रशासनिक राज्यकला (Statecraft): आधुनिक भारत की सुरक्षा का ढाँचा

भारत की अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFS आदि) जिन पर आज भारत की प्रशासनिक और सुरक्षा संरचना टिकी है, उन्हें संवैधानिक सुरक्षा पटेल ने दिलाई।

उनकी सोच थी की एक मजबूत, तटस्थ, केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र ही भारत को विघटन से बचा सकता है। पुलिस प्रशासन को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। राज्यों को स्वायत्तता मिले, पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक शांति पर कोई समझौता न हो।

उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि "यदि अखिल भारतीय सेवाएँ कमजोर हुईं तो देश की एकता और सुरक्षा संकट में पड़ेगी।"

आज भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, अलगाववादी आंदोलनों, राज्यों-केंद्र के बीच विवाद की पृष्ठभूमि में उनका यह मॉडल और अधिक प्रासंगिक हो गया है।

नेहरू-पटेल की नीति-दृष्टि में अंतर: यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद:

भारत की विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा के कई प्रश्नों पर पटेल और नेहरू के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर था:

नेहरू का दृष्टिकोण- नैतिकता पर आधारित अंतरराष्ट्रीयवाद, पंचशील, अहिंसक कूटनीति, चीन के प्रति विश्वास

पटेल का दृष्टिकोण- सीमाओं पर सुरक्षा-प्रधान नीति, शक्ति-संतुलन की राजनीति, सैन्य तैयारी और रणनीतिक चेतावनी, चीन के प्रति यथार्थवादी अविश्वास

SHABDBRAHM

पटेल ने 1950 में चेतावनी दी थी कि, "चीन भारत का दुश्मन है, मित्र नहीं।" नेहरू ने इस चेतावनी को आदर्शवाद के तहत अनसुना किया। 1962 का भारत-चीन युद्ध पटेल की यथार्थवादी चेतावनी को सत्य सिद्ध करता है।

समकालीन भारत-चीन सीमाई तनाव (डोकलाम, लद्दाख) पटेल की सुरक्षा-प्रधान नीति की प्रासंगिकता को पुनः सिद्ध करते हैं

आज का भारत और पटेल के राजनीतिक यथार्थवाद की आवश्यकता:

भारत जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे सभी पटेल के राजनीतिक मॉडल को नया महत्व देती हैं:

(क) आंतरिक सुरक्षा- आतंकवाद, माओवाद, उग्रवादी गतिविधियाँ, धार्मिक कट्टरता

पटेल का प्रशासनिक-सुरक्षा मॉडल इन चुनौतियों से निपटने के लिए अत्यंत उपयोगी है।

(ख) सीमाई विवाद- चीन, पाकिस्तान, समुद्री सुरक्षा पटेल की शक्ति-संतुलित विदेश नीति और मजबूत रक्षा ढाँचा आज भी सबसे व्यावहारिक विकल्प है।

(ग) पहचान-आधारित राजनीति- आज की भारतीय राजनीति में जाति-धर्म-भाषा आधारित राजनीति का बढ़ता प्रभाव उस एकीकृत भारत की अवधारणा को चुनौती देता है जिसे पटेल ने निर्मित किया था।

(घ) राष्ट्रीय एकता और संघीय स्थिरता- केंद्र-राज्य संबंधों में लगातार तनाव के बीच पटेल का "व्यावहारिक संघवाद" मॉडल एक संतुलन प्रदान करता है–

न तो अत्यधिक केंद्रीकरण, न ही अराजक विकेंद्रीकरण।

न्याय, सत्ता और राष्ट्र: पटेल के राजनीतिक विचारों की दार्शनिकता:

पटेल के विचारों की दार्शनिक पृष्ठभूमि निम्न प्रकार थी:

न्याय का अर्थ–सुरक्षा + व्यवस्था

सत्ता का अर्थ–राष्ट्रीय हितों की रक्षा

राष्ट्र का अर्थ–साझी पहचान + प्रशासनिक एकता

उनका मानना था कि,

"न्याय तभी संभव है जब राज्य की सत्ता संगठित और प्रभावी हो।"

यह दृष्टि आज के राजनीतिक विमर्श में कम चर्चा में रहती है, लेकिन लोकतंत्र को स्थिरता देने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यदि पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत कैसा होता? (वैकल्पिक विश्लेषण):

यह खंड अकादमिक "counterfactual methodology" पर आधारित है।

यदि 1947 में प्रधान नेतृत्व पटेल को मिला होता तो–

1. चीन नीति अधिक कठोर और यथार्थवादी होती, सीमाओं पर सैन्य तैयारी पहले से हो जाती, तिब्बत के प्रश्न पर भारत अधिक सशक्त रुख अपनाता
2. कश्मीर मुद्दे का समाधान सैन्य-कूटनीतिक संयोजन से होता, युद्ध विराम रेखा (LoC) की स्थिति अलग होती

3. पुलिस और प्रशासनिक ढाँचा और अधिक संगठित होता, आंतरिक सुरक्षा संकटों का स्वरूप अलग होता

4. पहचान-आधारित राजनीति सीमित रहती, राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाले आंदोलन प्रारंभ में ही नियंत्रित होते

5. विदेश नीति संतुलित होती, नैतिकता और शक्ति-राजनीति का संतुलन (Realpolitik) रहता

समकालीन इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग इस बात से सहमत है कि पटेल का नेतृत्व भारत को सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के मामले में अधिक मजबूत बनाता।

पटेल के साथ ऐतिहासिक अन्याय: राजनीति और वैचारिक संघर्ष:

स्वतंत्रता-उत्तर भारत के नेतृत्व में पटेल को अक्सर "दूसरी पंक्ति" में रखा गया।

इसके कई कारण थे:

कांग्रेस की वैचारिक राजनीति में नेहरूवादी समाजवाद का प्रभुत्व, सत्ता-संतुलन में गांधी का अंतिम निर्णय, ब्रिटिश अभिजात वर्ग का नेहरू के प्रति झुकाव, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेहरू की स्वीकार्यता,

SHABDBRAHM

परिणाम क्या हुवा –

पटेल की चेतावनियों को अनसुना किया गया, प्रशासनिक और सुरक्षा नीतियों में उनके विचारों को कम महत्व दिया गया, इतिहास-लेखन में उनकी भूमिका को अक्सर सीमित कर दिया गया

आज के भारत में यह आवश्यक है कि उनके योगदान का यथार्थवादी मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि भारतीय राज्य की स्थिरता का आधार उनके द्वारा निर्मित मॉडल पर टिका हुआ है।

संक्षिप्त में कहू तो-

सरदार पटेल का राजनीतिक यथार्थवाद केवल एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि

आज के भारत की राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य-निर्माण का सबसे प्रासंगिक मॉडल है।

उनकी नीतियाँ–कठोरता और लचीलापन, शक्ति और नैतिकता, संघवाद और सुरक्षा–इन सबके संतुलन पर आधारित थीं।

यही संतुलन आज के भारत को सर्वाधिक आवश्यकता है।

निष्कर्ष: "आज के भारत में राजनीतिक यथार्थवाद की प्रासंगिकता: सरदार पटेल का पुनर्विचार" विषयक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पटेल का राजनीतिक दृष्टिकोण केवल ऐतिहासिक प्रसंगों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक दूरदर्शी, व्यावहारिक और राष्ट्रकेंद्रित सोच का प्रतिनिधित्व करता था। आधुनिक भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है–राष्ट्रीय सुरक्षा, संघीय संतुलन, अलगाववादी प्रवृत्तियाँ, वैश्विक शक्ति-राजनीति, प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक-सामरिक हित–उन सभी के समाधान में पटेल के व्यवहारिकता-आधारित दृष्टिकोण की उल्लेखनीय प्रासंगिकता दिखाई देती है।

SHABDBRAHM

विशेष रूप से, रियासतों के एकीकरण में प्रदर्शित उनका साहस, त्वरित निर्णय-क्षमता और राजनयिक संतुलन आज भी नीति-निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं। पटेल ने सत्ता-राजनीति को राष्ट्रहित से जोड़ा, और भावनात्मक या वैचारिक आग्रहों के बजाय *व्यावहारिक परिणामों* को प्राथमिकता दी। आज की वैश्विक राजनीति, क्षेत्रीय विवादों और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह दृष्टिकोण और अधिक प्रासंगिक हो गया है।

अध्ययन यह निष्कर्ष देता है कि समकालीन भारत में राजनीतिक यथार्थवाद का पुनर्स्थापन केवल एक सैद्धांतिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक अनिवार्यता है। पटेल का मॉडल भारतीय लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़, उत्तरदायी और रणनीतिक बना सकता है।

इसलिए आवश्यक है कि उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण को आधुनिक राजनीतिक विमर्श, सार्वजनिक नीति-निर्माण और शासन-सुधारों में पुनः एकीकृत किया जाए।

संदर्भ सूचि (REFERENCE):

हिन्दी स्रोत (Hindi Sources)

1. शर्मा, रामस्वरूप. सरदार पटेल: लौहपुरुष और राष्ट्रीय एकता के शिल्पी. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 2015.
2. त्रिपाठी, अच्युतानंद. भारतीय राज्य का निर्माण और सरदार पटेल की भूमिका. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, 2019.
3. मिश्रा, प्रभात. भारत की रियासतें और एकीकरण: पटेल का दृष्टिकोण. वाराणसी: भारती प्रकाशन, 2016.
4. सिंह, रविंद्र. "राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय एकता में सरदार पटेल का योगदान." राजनीति विज्ञान समीक्षा, खंड 42, अंक 3, 2020.
5. गुप्ता, नवल. "समकालीन राजनीति में पटेल की प्रासंगिकता." इंडियन पॉलिटिकल जर्नल, 2018.
6. भारतीय स्वतंत्रता संग्रहालय अभिलेखागार. हैदराबाद और जूनागढ़ एकीकरण दस्तावेज़ संग्रह. नई दिल्ली, भारत सरकार प्रकाशन विभाग.

English References:

1. Copland, Ian. The Princes of India in the Endgame of Empire, 1917-1947. Cambridge University Press, 1997.
2. Menon, V.P. The Story of the Integration of the Indian States. Orient Blackswan, 1956.
3. Hardgrave, Robert L. "Sardar Patel and the Indian State Formation." Journal of Asian Studies, Vol. 38, No. 4, 1979.

4. Brown, Judith M. Modern India: The Origins of an Asian Democracy. Oxford University Press, 1994.
5. Guha, Ramachandra. India After Gandhi. HarperCollins, 2007.
6. Brass, Paul. The Politics of India Since Independence. Cambridge University Press, 1994.
7. Noorani, A.G. "The Hyderabad Question Revisited." Economic & Political Weekly, 2003.
8. Smith, Donald E. India as a Secular State. Princeton University Press, 1963.
9. Bipan Chandra et al. India's Struggle for Independence. Penguin, 1989.

ગુજરાતી સ્રોત:

SHABDBRAHM

1. પટેલ, રમેશચંદ્ર. સરદાર પટેલ: રાષ્ટ્રીય એકતા ના શિલ્પી. અમદાવાદ: જીવન પ્રકાશન, 2013.
2. ઠાકોર, કનુભાઈ. ભારતનું રજવાડું એકતાવલણ અને સરદાર પટેલ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, 2018.
3. પરીખ, હર્ષદ. "આધુનિક ભારતના રાજ્ય નિર્માણમાં સરદાર પટેલનું યોગદાન." ગુજરાત પૉલિટિકલ સાયન્સ જર્નલ, 2020.
4. પટેલ, ભીખાભાઈ. લોખંડી મનુષ્ય: સરદાર પટેલ. અમદાવાદ: યુનિવર્સલ પબ્લિકેશન, 2016.
5. ગાંધીનગર અભિલેખાગાર. હૈદરાબાદ અને જુનાગઢ એકીકરણના દસ્તાવેજો, ગુજરાત સરકાર પ્રકાશન.

शोध लेख (Articles / Papers):

चौबे, सुनील. "भारतीय संघवाद और पटेल की प्रशासनिक दृष्टि." लोकनीति अध्ययन, 2021.

मिश्रा, विनय. "पटेल और नेहरू: नीतिगत टकराव और राष्ट्रीय हित." हिंदी पॉलिटिकल स्टडीज जर्नल, 2019.

Jalal, Ayesha. "State Formation in South Asia." Comparative Studies in Society and History, 1995.

Varshney, Ashutosh. "National Integration and the Indian State." World Politics, 1998.

દેસાઈ, નિરવ. "સમકાલીન ભારતની સુરક્ષા માન્યતાઓ અને પટેલની નીતિઓ." સામાજશાસ્ત્ર અને રાજનીતિ, 2022.

सरकारी दस्तावेज़ / Official Documents

Constituent Assembly Debates (1946-1950) - भारत की संविधान सभा में पटेल के भाषण.

Ministry of Home Affairs (GOI) - Integration of Princely States Reports, 1948-1950.

National Archives of India - Patel Correspondence Series.